

उत्तराखण्ड शासन,  
परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग-2  
संख्या-319/ix/न०३/2007  
देहरादून :दिनांक 02 जुलाई, 2008

कार्यालय ज्ञाप

जौलीग्राण्ट स्थित विमानन परिसर में स्टेटएन्क्लोजर के अंतर्गत नवनिर्मित वी0आई0पी0 भवन की साज-सज्जा तथा उपकरणों की आपूर्ति किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-186/ix/190/2008 दिनांक 31 मार्च 2008 एवं में शासनादेश संख्या-187/ix/190/2008 दिनांक 31 मार्च 2008 के द्वारा दी गई स्वीकृति के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को यूनिट स्तर पर एक कय समिति गठित कर यह कार्य विस्तृत बाजार सर्वेक्षण के उपरान्त प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से सम्पादित कराने की कार्यवाही वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-195/xxxi(7)/2008 दिनांक 13 मई 2008 के साथ संलग्न उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2008 के अनुरूप किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- इस संबंध में कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम की यूनिट स्तर पर गठित कय समिति में श्री जी0 सित्तैया, अपर निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता को नागरिक उड्डयन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया जाता है।

( पी0सी0 शर्मा )  
प्रमुख सचिव।

संख्या-319/ix/न०३/2008 तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, वी0आई0हैंगर, जौलीग्राण्ट,, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 2- मुख्य अभियन्ता एवं अपर निदेशक(श्री जी0 सित्तैया,) नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- परियोजना प्रबंधक, श्री एस0सी0जैन, कन्सल्ट्रक्सन विंग ऋषिकेश, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
- 4- महाप्रबंधक नोडल निर्माण विंग उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- 5- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड सचिवालय,
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( विनोद शर्मा ) 2/7  
अपर सचिव।

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 2766 /प्रमुख सचिव,दिनांक 13-5-08

देहरादून, दिनांक 13 मई, 2008

वित्त अनुभाग-7

विषय: उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 के संबंध में।  
गहोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2008, 1 मई 2008 को अधिसूचित कर दी गयी है। अतः वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-एक तथा समय समय पर निर्गत शासनादेश द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों की सीमा में सक्षम स्तर से प्रोक्योरमेन्ट की प्रक्रिया उपरोक्त नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाए। वित्त विभाग को मात्र वही प्रकरण संदर्भित किये जायें जिरामें पूर्व से वित्तीय नियमों के अधीन वित्तीय प्रतिनिधायन न हो, नियमावली में दिये गये विवरण पर कोई स्पष्टीकरण वांछित हो अथवा नियमावली में चिन्हित विशिष्ट परियोजनाओं/कार्यों हेतु अधिप्राप्ति में निर्धारित प्रक्रिया में शिथिलता आवश्यक हो। यह नियमावली इन्टरनेट की साइट: [www.ua.nic.in](http://www.ua.nic.in) पर फाइनैन्स विलक करने पर उपलब्ध है।

कृपया उपरोक्त के कम में उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 जो तद्विषयक अन्य नियमों पर आधारित प्रभाव रखता है, को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय।  
संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)  
प्रमुख सचिव

संख्या /XXXII(7)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1: महालेखाकार, ओबराय विल्डिंग सहायपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड।
- 2: समस्त विभागाध्यक्ष, जिन कार्यालयों में उत्तराखण्ड शासन का कार्यालय है।
- 3: सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 4: रजिस्ट्रार जनरल माओ उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 5: रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
- 6: समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 7: उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(टी०एन०सिंह)  
अपर सचिव

(श्री.सी. रामा)

प्रमुख सचिव  
न्यायिक एवं न्याय विभाग  
उत्तराखण्ड शासन

अपर सचिव  
न्यायिक सचयन  
उत्तराखण्ड शासन

17-06-08